नई शिक्षा नीति (2016-17-18) के
नए जुमलों, नए हमलों, नए खतरों

•

शिक्षा का

पूरा कारपोरेटीकरण, केंद्रीकरण व सांप्रदायिकीकरण

•

राज्य सरकारों के संवैधानिक हक छीनने का षड़यंत्र

•

बहुजन, मज़दूर वर्ग व अन्य सभी मेहनतकश तबकों,
खासकर लड़कियों, विकलांगों, ट्रांस-जेंडरों, विमुक्त व घुमंतू जातियों का

शिक्षा से महा-निष्कासन

इस बहुजन-विरोधी व संविधान-विरोधी एजेंडे के खिलाफ़
समता व सामाजिक न्याय को लागू करती संविधान-सम्मत
'केजी से पीजी' तक मुफ़्त • निजीकरण से मुक्त • बगैर किसी भेदभाव के

समान शिक्षा व्यवस्था

कायम करने के लिए

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम) के आह्वान पर

18 फरवरी 2019* • दिल्ली • हुंकार रैली

शिक्षा बचाओ! संविधान बचाओ!!
देश बचाओ! देश बचाओ!!

•

सबको शिक्षा एक समान, लड़कर लेगा मज़दूर किसान!

संपर्क: मो. 9407549240, 7024148240; ईमेल: aifrte.secretariat@gmail.com; वेबसाइट: www.aifrte.in

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच 22 राज्यों के 75 से भी ज़्यादा छात्र-शिक्षक संगठनों व शैक्षिक अधिकार संघर्षशील समूहों का मंच है। इस आंदोलन के अभियान-साथी और सदस्य-संगठन बनें!

***जो संगठन 19 फरवरी 2019 को जेएफ़एमई (Joint Forum for Movement on Education) द्वारा दिल्ली में आयोजित किए जा रहे संसद मार्च में बिरादराना संगठन बतौर शामिल होना चाहते हैं, वे उसके मद्देनज़र अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं।**

अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम) का आह्वान

18 फरवरी 2019* को

संविधान की बुनियाद पर खड़ी शिक्षा के हक के लिए दिल्ली में आयोजित

हुंकार रैली में शामिल हों

हुंकार रैली क्यों >>>

- शिक्षा के निजीकरण, बाज़ारीकरण, सांप्रदायिकीकरण व केंद्रीकरण (राज्यों के हक छीनने) के खिलाफ़;
- दलितों, आदिवासियों और धार्मिक-भाषाई अल्पसंख्यकों समेत सभी बहुजनों (यानी 85 फ़ीसद आबादी) को शिक्षा से बाहर (महा-निष्कासन) कर रही नवउदारवादी-ब्राह्मणवादी-पितृसत्तात्मक नीतियों के खिलाफ़;
- लड़कियों, विकलांगों, ट्रांस-जेंडरों, विमुक्त व घुमंतू जातियों का शिक्षा का संवैधानिक हक छीनने के खिलाफ़;
- शैक्षिक संस्थानों में अभिव्यक्ति, विचार, आस्था व संगठित होने की आज़ादी छीनने की साजिश के खिलाफ़;
- 'केजी से पीजी तक' समतामूलक गुणवत्ता की सरकार द्वारा वित्त-पोषित, हर तरह के भेदभाव से मुक्त, पूरी तरह मुफ़्त 'समान शिक्षा व्यवस्था' ('केजी से 12वीं कक्षा तक समान स्कूल व्यवस्था' समेत) के लिए;
- शिक्षा से विषमताओं (गैर-बराबरियों) को बाहर करने और विविधताओं को शामिल करने के लिए;
- शिक्षा को विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन-गैट्स व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की विभिन्न एजेंसियों से मुक्त करने के लिए;
- गैर-बराबरी व भेदभाव फैलानेवाली; सामाजिक न्याय छीननेवाली; जाति-व्यवस्था व पितृसत्ता को मजबूत और लोकतंत्र को कमज़ोर करनेवाली इस संविधान-विरोधी शिक्षा व्यवस्था को आमूलचूल बदलकर परिवर्तनकामी, मुक्तिदायी, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए.

सबको शिक्षा एक समान, लेकर रहेगा बहुजन अवाम!

हुंकार रैली की मुख्य मांगें >>>

- सरकारी शैक्षिक संस्थानों को बेहतर बनाओ – प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों पर लगाम कसते हुए उनका राष्ट्रीयकरण करो;
- शिक्षा में मुनाफ़ाखोरी, धंधेबाजी व एनजीओकरण खत्म करो; शैक्षिक कर्ज़ नहीं, सामाजिक न्याय का एजेंडा लागू करो;
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश (अगस्त 2015) को केंद्रीय कानून बनाकर पूरे देश में लागू करो जिसके तहत सरकार से पैसा पाने वाले हरेक व्यक्ति - यानी प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों/विधायकों व आईएएस-आईएफ़एस-आईपीएस अफ़सरों व सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जजों से लेकर चपरासी तक और सड़कों-खदानों, आईटी व अन्य उद्योगों के सरकारी ठेकेदारों - को अपने बच्चों को पड़ोस के सरकारी स्कूल भेजना कानूनन अनिवार्य हो;
- जो बच्चे 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में पढ़ें उनको सरकारी विश्वविद्यालयों व प्रोफ़ेशनल शैक्षिक संस्थानों के दाखिलों और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता देने का कानून बनाओ ताकि सभी वर्गों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगें और सभी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों के समकक्ष बनाने के लिए सरकार मजबूर हो जाए;
- सरकारी व निजी दोनों शैक्षिक संस्थानों में उम्दा ज्ञान-विज्ञान व बढ़िया अंग्रेजी सिखाने के लिए मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम कानूनन बनाओ - इंग्लिश मीडियम के बहाने भावी पीढ़ियों की शिक्षा बर्बाद करने की धोखाधड़ी बंद करो;
- पत्राचार कोर्स वाली शिक्षा व्यवस्था (स्कूल ऑफ़ ओपन लर्निंग आदि) के बहाने उत्पीड़ित वर्गों/जातियों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से वंचित करने की साजिश बंद करो;
- शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 10% खर्च करो जब तक कि साल-दर-साल चौड़ी होती खर्च की खाई पट न जाए;
- 'भारत का उच्च शिक्षा आयोग विधेयक' (HECI Bill) व 'राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक' (NMC Bill) वापस लो.

बराबरी (आर्थिक बराबरी समेत), भेदभाव से मुक्त, सामाजिक न्याय, विविधता, विचार-आस्था-अभिव्यक्ति की आज़ादी व लोकतांत्रिक हकों के लिए संविधान के मुताबिक शिक्षा की हुंकार

शिक्षा बचाओ! संविधान बचाओ!! देश बचाओ!!!

***जो संगठन 19 फरवरी 2019 को जेएफ़एमई (Joint Forum for Movement on Education) द्वारा दिल्ली में आयोजित किए जा रहे संसद मार्च में बिरादराना संगठन बतौर शामिल होना चाहते हैं, वे उसके मद्देनज़र अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं।**